



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170]

नई दिल्ली, बुधवार, 6 मई, 1981/वैसाख 16, 1903

No. 170)

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 1981/VAISAKHA 16, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या ही जाती है। जिससे कि यह अलग संकलन के लिए इसमें रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

कृषि और सहकारिता विभाग

अधिकृतमा

नई दिल्ली, 6 मई, 1981

सा० का० नि० 322 (अ.):—कृषि विभाग, नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 (1979 का 5) की धारा 19 की उपधारा (2) के खण्ड (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, प्रयत्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नारियल विकास बोर्ड (विकल्प प्रखण्ड) नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख की प्रकृत ही हैं।

2. परिभाषाएः:—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अस्थिया प्रयोजित न हो:

(अ) 'अधिनियम' से नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 (1979 का 5) अभिप्रेत है।

(ब) "प्रखण्ड" से इन नियमों से उपायद प्रखण्ड अभिप्रेत है।

3. अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन विकल्प प्रखण्ड:

अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) में निषिद्ध विकल्प का प्रयोग नारियल विकास निवेशालय के अधिकारियों और भव्य कर्मचारियों द्वारा प्रखण्ड I या II में इनमें जो भी मनुष्यित हो,

ऐसे समय के भीतर, जो केवल सरकार द्वारा इस नियमित विनियिष्ट किया जाए, नारियल विकास बोर्ड का कर्वंचारी होने की अननी रजामन्दी अभिष्वक्त करते या अस्थिया के लिए किया जाएगा और एक बार प्रयोग किया गया ऐसा विकल्प अनुमति होगा।

[फा० सं० 12-15/78-सी० ए०-१]
प्रार० सी० सू०, प्रपर सचिव

प्रखण्ड
(नियम 3 देखिए)

सेवा में,

कृषि, भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
कृषि और सहकारिता विभाग
नई दिल्ली।

महोदय,

भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) के पठ संघर्षा —————— नारीक —————— के संरभ में मैं, श्री/श्रीमती/कु^o—

- (d) रकम, यदि कोई है, जो पहले ही प्राप्त की गई है, और उसकी विविधियाँ;
 - (e) ऐसे दावे से सुनांगत कोई अन्य विविधियाँ;
 - (f) अनुतोष, विसका बाबा किया गया है।
- (2) प्रत्येक सूचना, वंशकदार या ऐसा भाइ, धारणाविकार या अन्य क्षिति वाले वाले अवित या ऐसे अपित द्वारा सम्पक रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सम्पक रूप से हस्ताक्षर की जाएगी, और सत्यापित की जाएगी।
- (3) सूचना, आमुक्त के कलंकता या मुम्बा स्थित कार्यालय या, सभी कार्य क्लिंबों में, कार्यालय के समय के बीच काइस की जाएगी या आमुक्त को रखी रखिस्ती आक द्वारा भेजी जाएगी।

[प्रा० सं० प्राइ० एम ई-49(10) 81]
मनोज बहल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 1981

S.O. 228(E).—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Hind Cycles Limited and Sen-Raleigh Limited (Nationalisation) Act, 1980 (70 of 1980), the Central Government hereby makes the following rules namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Hind Cycles Limited and Sen-Raleigh Ltd. (Nationalisation) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

- (a) "Act" means the Hind Cycles Limited and Sen-Raleigh Limited (Nationalisation) Act, 1980.
- (b) 'section' means a section of the Act..

3. Time-limit for intimation.—Every mortgagee of any property which has vested under the Act in the Central Government or in a Government Company, as the case may be, and every person holding any charge, lien or other interest in, or in relation to, any such property shall give intimation of such mortgage, charge, lien, or other interest to the Commissioner within a period of thirty days from such date, as may be specified by the Central Government under section 18 :

Provided that if the Commissioner is satisfied that the mortgagee of the person holding any charge, lien or other interest was prevented by sufficient cause from giving the intimation within the said period of thirty days, he may, after recording reasons in writing receive the intimation within a further period of thirty days and not thereafter.

4. Manner of intimation.—(1) Every intimation to be given to the Commissioner under rule 3 shall be in writing addressed to the Commissioner, and shall contain the following particulars, namely :—

- (a) Name, description and full address of the mortgagee/ charge, lien or other interest holder ;
- (b) Name of the undertaking in respect of which the claim is made ;
- (c) amount of claim (in Indian currency) ;
- (d) particulars of the instrument, if any, by which the mortgage, charge, lien or other interest is secured, supported by an attested copy of the instrument ;
- (e) amount, if any, already received, with particulars ;
- (f) any other particulars relevant to the claim ;
- (g) relief claimed.

(2) Every intimation shall be duly signed and verified by the mortgagee, or the person holding the charge, lien or other interest or by a person duly authorised by him.

(3) Intimation may be filed in the office of the Commissioner at Calcutta or Bombay on all working days during office hours or may be sent to the Commissioner by registered post with acknowledgement due.

[File No. IME-49(10)/81]
MANISH BAHL, Jt. Secy.